

**Fourteenth Loksabha**

**Session : 6**

**Date : 09-12-2005**

**Participants :** [Dasmunsi Shri Priya Ranjan](#),[Radhakrishnan Shri Varkala](#),[Virendra Kumar Shri](#),[Patil Adv. Tukaram Ganpatrao Renge](#),[Murmu Shri Hemlal](#),[Jatiya Dr. Satyanarayan](#),[Prasad Shri Hari Kewal](#),[Rawat Shri Bachi Singh](#),[Ahir Shri Hansraj Gangaram](#),[Mohale Shri Punnulal](#)

>

Title : Regarding Governemnt Business for the week commencing 12<sup>th</sup> December, 2005 and submission by members.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 12<sup>th</sup> of December, 2005 will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2005-06 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
3. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) (Second) for 2005-06 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
4. Consideration and passing of the following Bills after they have been passed by Rajya Sabha:-
  - (i) The Criminal Law (Amendment) Bill, 2003;

- (ii) The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2005;
- (iii) The Cost and Works Accountants (Amendment) Bill, 2005; and
- (iv) The Company Secretaries (Amendment) Bill, 2005.

MR. SPEAKER: Shri Chandra Sekhar Sahu -- Not present.

Shri Varkala Radhakrishnan.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Sir, I would like to submit that the following items may be included in the next week's agenda:

1. Central Government shall take steps for giving exemptions in guidelines for starting Kerala Airlines as proposed by the State.
2. Immediate steps be taken towards the establishment of a bench of Kerala High Court at Trivandrum.

श्री वीरेन्द्र कुमार बीना नगर में दूरदर्शन केन्द्र नहीं होने से जनता को काफी कठिनाइयों का अनुभव होता है, अतः शीघ्र ही बीना में दूरदर्शन केन्द्र आरम्भ करने की कार्यवाही की जाए।

सागर में बीड़ी मजदूर अस्पताल लगभग बनकर पूर्ण होने जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के बीड़ी मजदूरों को अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ होगा, अतः डाक्टरों एवं विशेषज्ञों की विशेष नियुक्ति कर अस्पताल शीघ्र मरीजों की सुविधा के लिए प्रारम्भ किया जाए।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी एवं शिक्षकगणों को पेन्शन सुविधा दिए जाने का कार्य।

मराठावाडा क्षेत्र में बीएसएनएल की असंतोजनक दूरसंचार सेवा को दुरुस्त एवं बीएसएनएल की मोबाईल सेवा के लिए सिमकोर्ड उपलब्ध करवाए जाने का कार्य।

श्री हेमलाल मुर्मू झारखंड विद्युत बोर्ड द्वारा 4925 गाँवों में विद्युतीकरण हेतु 300 करोड़ रूपए की निविदा र्वा 2003 में रेलवे की एक कम्पनी राइट्स को देने के पश्चात सबलेट कर एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देशों की अ वहेलना कर एक अनुभवहीन स्थानीय कम्पनी रामजी पावर कंस्ट्रक्शन को निविदा राशि का 92.5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर देने के बाबत जांच करने और झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को एक निर्धारित सीमा के अन्दर पूरा करने की अपेक्षा।

हाल में झारखंड के 16 जिलों में " काम के बदले अनाज कार्यक्रम " योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन बंद करने की योजना को पुनः चालू कराने तथा झारखंड राज्य के पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा आदि जिलों में उक्त इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की नियमित उठान एवं आपूर्ति सुनिश्चित कराने की अपेक्षा।

डॉ. सत्यनारायण जटिया महोदय मैं अपना वक्तव्य संस्कृत में देना चाहूंगा।

केन्द्रसर्वकारेण द्विसहस्रएकात् वार्त् या कृति-श्रमिक-सामाजिक-सुरक्षा योजना प्रारंभिता तस्यै आवश्यकम् धनराशिम् प्रदेयम्। कृति-श्रमिकेभ्यः तोाम् आश्रितेभ्यः अपि च दुर्घटनायाम् विमावस्थायाम् च आर्थिक-सहायताम् च दातव्यम्।

विश्वव्यापारसंगठनस्य या मंत्रिस्तरीया वार्ता हांगकांग-नगर्याम् भवियति तस्याम् दोहरायाः वार्तायाः पृ-ठभूम्याम् प्रासंगिकेु संदर्भेु च विकासशीलानाम् न्यूनतम विकसितदेशानाम् च हितानाम् संरक्षणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। एतदर्थम् भारतस्य अन्यानाम् विकासशीलदेशानाम् न्यूनतमविकसितदेशानाम् च कृति-कृयेतराणाम् उत्पादानाम् च हिताय याः अपि विसंगत्याः सन्तिः ताः निवारयितुम् स्वदेशस्य अन्यानाम् विकासशीलदेशानाम् च हिताय संरक्षणम् आवश्यकम्।

MR. SPEAKER: धन्यवादम्। I was a good student of Sanskrit but I have forgotten it now.

श्री हरिकेवल प्रसाद अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में राजभर, मल्लाह, बिन्द प्रजापति एवं केवट जातियां बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है एवं बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है। उत्तर प्रदेश

सरकार ने 14 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने हेतु अधिसूचना भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का अनुरोध भी किया है जो काफी समय से लंबित है। इस प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने का कार्य किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के जिला देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से 40 गांवों को डूबने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने का कार्य किया जाए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल के पिथौरागढ़ नगर के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत सीवरेज योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता।

पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व चम्पावत के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सड़क निधि व राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता।

श्री हंसराज जी.अहीर अध्यक्ष महोदय, बडसा-आरमोदी-गडचिरोली सर्वेक्षित रेल मार्ग पर पटरी बिछाने के लिए 77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। इस क्षेत्र के जनजातीय बहुल क्षेत्र में रेल सेवा के अभाव के कारण विकास में आए गतिरोध को दूर करने के लिए उक्त रेल मार्ग पर पटरी बिछाना आवश्यक है। इसी तरह आदिवासी क्षेत्र में रेल परिचालन के लिए रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास होने चाहिए।

चंद्रपुर स्टेशन जिला मुख्यालय तथा उद्योग बहुल केन्द्र होने के बावजूद यहां से लंबी दूरियों की गाड़ियों के ठहराव अल्प हैं। यहां की महत्ता देखते हुए केरल, तमिलनाडु, राजधानी, नागपुर के बीच में शटल ट्रेन चलाए जाने की जरूरत है।

श्री पुन्नू लाल मोहले अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर चलने वाली चिरमिरी- बिलासपुर लोकल ट्रेन को चिरमिरी से मगेण्ड-बिलासपुर-रायपुर-दुर्ग तक बढ़ाया जाए जिससे उक्त क्षेत्र के 100 ग्रामों के लोगों को मगेण्डगढ़

तक आने-जाने की सुविधा होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य अरपामैसा झील परियोजना सिंचाई जो केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है जिस के बनने से 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी एवं तरवतपुर, गुगेली, लोरपी, कोटा, बिल्हा आदि ब्लॉक जिला बिलासपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

---